साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 22-28 अगस्त 2022, वर्ष-8, अंक-20

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

-कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने किसानों को दी राहत

किसानों को तीन लाख तक के लोन पर 1.5 फीसदी की छूट

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी 5 लाख करोड़ किया

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार लगातार किसानों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। बैठक में तीन लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5 फीसदी की छूट को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत साल 2022-23 से 2024-25 के बीच में 34,856 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले से किसानों को कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त ऋण मिल सकेगा। सरकार ने किसानों को ऋण में छूट देने के साथ ही क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कोष को भी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम से कृषि क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम किसानों को पहले दिन से प्राथमिकता दे रहे हैं। किसानों को केडिट कार्ड पर छोटी अवधि के लिए तीन लाख रुपए का कर्ज मिलता है। इस पर सात फीसदी की दर से ब्याज चुकाना होता है। अगर किसान सही समय पर इसका भुगतान करते हैं तो उन्हें तीन फीसदी की छूट मिलती है। यानी किसानों को मात्र चार फीसदी की दर से ही ब्याज देना होता है। छोटी-बड़ी और क्षेत्रीय-ग्रामीण जैसी अलग-अलग बैंकों की तरफ से किसानों को यह सुविधा मिलती है। मई 2020 में बैंकों को सरकार की ओर से दो फीसदी छूट की मदद मिलना बंद कर दी गई थी क्योंकि तब ब्याज दरें कम थीं।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी 5 लाख करोड़ किया
34,856 करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया

रेपो रेट से किसानों पर असर नहीं

अब आरबीआई ने दो बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। किसानों पर ब्याज दर का ज्यादा बोझ न पड़े या फिर जो बैंक किसानों को सात फीसदी की ब्याज दर से कर्ज देते हैं, उन पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि वह ब्याज दर में डेढ़ फीसदी की सहायता करेगी। यह मदद वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक रहेगी। किसानों को पहले की तरह सात फीसदी की दर से कर्ज मिलता रहेगा।।

सबवेंशन स्कीम

सरकार की ओर से सहकारी समितियों और बैंकों के जरिए किसानों को कम ब्याज दर पर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता है। इस लोन को कई किसान समय पर चुका देते हैं और जबकि काफी किसान किसी कारणवश समय पर नहीं चुका पाते। जो किसान समय पर लोन चुका देते हैं, उन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा।

इस निर्णय से स्थानीय एवं सहकारी बैंकों की हालत सुधरेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। किसानों को अपनी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए और अधिक धन उपलब्ध होगा। यह निर्णय कृषि क्षेत्र में नवीन रोजगार उत्पन्न कर कृषक कर्मवीरों की जिंदगी बदलने का काम करेगा। तीन लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5 फीसदी प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता को मंजूरी देने और 34856 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन के लिए पीएम एवं केन्द्रीय कैबिनेट का हार्दिक आभार और अभिनंदन।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मप्र

यह ऋण किसानों को सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कृषि और संबद्ध गतिविधियों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध है। इसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन आदि शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कई ऋण देने वाली संस्थाओं को 3.00 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋण पर 1.5 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज सबवेंशन का निर्णय लिया। सरकार की इस पहल का किसानों का सबसे अधिक फायदा मिलेगा। किसान छोटे व्यवसायों के लिए अल्पावधि कृषि ऋण कम ब्याज में पा सकेंगे।

नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री

किसान और कृषि के समग्र उत्थान के लिए कृत-संकल्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-2025 के लिए तीन लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋण पर 1.5 फीसदी वार्षिक ब्याज अनुदान को स्वीकृति प्रदान की है। इससे किसानों को अल्पकालिक कृषि आवश्यकताओं के लिए लोन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिक से अधिक किसानों को कृषि ऋण का लाभ मिलेगा। इससे रोजगार का भी सृजन होगा। किसान प्रोत्साहित होंगे।

कमल पटेल, कृषि मंत्री, मप्र

कृषि विविधीकरण: किसानों से करवाएंगी उद्यानिकी और औषधीय खेती

प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाएंगी 12 कंपनियां

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में किसानों को गेहूं और धान जैसी परंपरागत फसलों के बजाय उद्यानिकी और औषधीय फसलों की खेती करने के लिए 12 कंपनियां प्रोत्साहित करेंगी। कृषि विविधीकरण योजना के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में 6.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस तरह से खेती करवाई जाएगी। कंपनियां किसानों को फसल उत्पादन का प्रशिक्षण देंगी। बीज भी उपलब्ध कराएंगी। उपज खरीदने के साथ भंडारण भी कंपनियां ही करेंगी। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट रखा है। किसानों को लाभकारी खेती की ओर उन्मुख करने के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने का निर्णय किया गया है। किसानों को ऐसी फसल उपजाने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिनकी कीमत बेहतर मिलती है। इस योजना में अब तक 12

फायदे: फसल बीमा होगा, बीज-खाद कंपनियां देंगी

- किसान और कंपनी के बीच आपसी सहमति से खेती होगी।
- उपज की दर दोनों मिलकर तय करेंगे।
- जो उपज होगी, उसे कंपनी खरीदेगी।
- भंडारण, परिवहन आदि व्यवस्था भी कंपनी करेगी।
- किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ बीज-खाद आदि कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।
- खेती का अन्य काम किसान के जिम्मे होगा। इससे कंपनियों को अपेक्षित गुणवत्ता की उपज मिल सकेगी।
- किसान को फसल खराब होने के जोखिम से बचाने के लिए बीमा कराया जाएगा।
- प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रविधान अनुसार राहत भी मिलेगी।
- किसान के साथ कंपनियां जो भी वादा करेंगी, उसका ब्योरा सरकार को देंगी ताकि दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रहें।

दो को मिली अनुमति दो को अनुमति दी जा चुकी है। कृषि विभाग 10 अन्य कंपनियों के प्रस्तावों का परीक्षण कर अंतिम रूप दे रहा है। दरअसल, प्रदेश में अधिकांश किसान गेहूं, धान जैसी परंपरागत फसलों की खेती करते हैं। इनमें आय सीमित होती है, जबकि उद्यानिकी व औषधीय फसलों की खेती में लाभ अधिक है, लेकिन चुनौती बाजार मिलने व भंडारण की आती है। इसके हल के लिए सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना बनाई है।

मप्र में अतिवृष्टि से खरीफ फसलों को नुकसान

सोयाबीन, मूंग, उड़द, तुअर, मक्का, सब्जी सहित अन्य फसलें प्रभावित

भोपाल। मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही वर्षा से खरीफ फसलों को नुकसान की स्थिति बनने लगी है। खेतों में पानी भरा हुआ है। इससे सोयाबीन, मूंग, उड़द, तुअर, मक्का, सब्जी सहित अन्य फसलें प्रभावित हो रही हैं। कृषि विभाग ने किसानों को खेत से पानी निकालने की व्यवस्था बनाने की सलाह दी है। यदि यही स्थिति बनी रहती है तो फसलें गलने लगेंगी। पूर्व कृषि संचालक डॉ.जीएस कौशल का कहना है कि धान और गन्ना के लिए यह वर्षा लाभप्रद है। सोयाबीन सहित अन्य फसलें अधिक समय तक पानी में नहीं रह सकती हैं। भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, हरदा सहित अन्य जिलों में अधिक वर्षा से फसलें प्रभावित हुई हैं। वहीं, अपर मुख्य सचिव कृषि अजीत केसरी का कहना है कि अभी तक फसल प्रभावित होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। किसानों को खेतों से पानी निकालने के लिए कहा जा रहा है।

हाथों में खराब फसलें लेकर पहुंचे तहसील, नारेबाजी कर की मुआवजे की मांग

बारिश से किसान बर्बाद

सागर। जागत गांव हमार

सागर संभाग के बीना में खराब फसल हाथों में लेकर बड़ी संख्या में किसान नारेबाजी करते हुए बीना के तहसील परिसर पहुंचे। किसानों की हाल ही में चार दिनों तक हुई बारिश से कई गांव की फसल खराब हो गई। किसानों ने सर्वे कर मुआवजे की मांग प्रशासन से की है।

किसानों ने बताया कि 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक बेतवा नदी में लगातार बारिश होने के कारण बांधों के डेमो से पानी छोड़ा गया है। बेतवा नदी उफान पर आ गई और नदी से लगे खेतों में पानी भरने के कारण सोयाबीन, उड़द की फसल खराब हो गई। जिसकी किसानों ने जांच कर उचित मुआवजा राशि की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम एसडीएम शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है।

इन गांव की फसलें हुईं खराब

बांधों से पानी छोड़ने के कारण बेतवा नदी के किनारे लगे हुए हांसलखेड़ी, ढिमरोली, हांसुवा, धरमपुर, बेसरा, बाघारूपा, ढाना, लखाहर, सिरचोपी, खमउखेड़ी, हिरौद, गोची, बगसपुर, दौलतपुर, कंजिया, सलिता, रमपुर, पिपरासर गांवों के खेतों में बाढ़ का पानी आ गया। जिससे फसल खराब हो गई।

किसानों ने सौंपा ज्ञापन

कई किसानों ने तहसील परिसर पहुंचकर एसडीएम शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से जितेंद्र सिंह, सुदामा, विष्णु प्रसाद, रामनरेश सिंह, रघुराज सिंह, मुन्नालाल, नरेंद्र सिंह, विशाल सिंह, माखन सिंह, विजय सिंह, विमला अहिरवार सहित कई लोग मौजूद थे।

जबलपुर। इन दिनों मौसम ऐसा है कि पानी कब कहां गिरने लगे कुछ पता नहीं। झमाझम बारिस ने खेतों को लबालब कर दिया। खेतों में कृषि कार्य चालू हैं। कृषि कार्य से जुड़े लोगों का मानना है कि इस वक्त का मौसम धान के लिए सर्वोत्तम है। धान की रोपाई का काम हो चुका है। उसके पौधों को मजबूत बनाने के लिए इस समय गिर रहा पाना अमृत-वर्षा के समान है। किसान इस दिनों होने वाली वर्षा के पानी को खेतों में कुछ समय तक और रोकना चाहेंगे। ताकि पौधे की पानी संबंधी जरूरत पूरी हो जाए। हालांकि अगर वर्षा ऐसे ही चार-छह दिन और जारी रही तो धान को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसके विपरीत मूंग-उड़द के लिए भी यह पानी अब खतरे की घंटी बजा रहा है। खेत भर चुके हैं। उनको खाली करने की नौबत आ चुकी है। अगर वो खेतों में पानी भरा रहने देंगे तो मूंग-उड़द के पौधे सड़ने लगेंगे।

इस समय का मौसम धान के लिए यह पानी बहुत उपयोगी है। लेकिन बीते हफ्ते भर से पानी ज्यादा गिर रहा, इसलिए उड़द-मूंग और तिलहनों के लिए यह खतरा हो सकता है।

-एसके निगम, उप संचालक-कृषि

कम लोग ही कर रहे खेती

अच्छी बात यह है कि जबलपुर जिले में उड़द और मूंग की खेती इस सीजन में बहुत कम लोग करते हैं। मझौली जनपद सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में इस सीजन में उड़द और मूंग की फसल ली जा रही है। इसी तरह से तिलहनों के लिए भी लगातार गिरने वाला पानी खतरा माना जाता है। जहां-जहां तिली, सरसों या सोयाबीन लगा है वहां अगर वर्षा-जल के निकासी का पर्याप्त इंतजाम नहीं हुआ तो फसलों को नुकसान होने की आशंका गहरा गई है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों के दौरान भी मौसम ऐसा ही रहा तो तिलहनों को नुकसान पहुंच सकता है।

न्यूनतम 300 से 500 रुपए क्विंटल तक बिक रहा लहसुन

रतलाम में लहसुन की बंपर आवक के बाद भी गिरे दाम

रतलाम।

रतलाम जिले में लहसुन का बंपर उत्पादन करने वाले किसान अब लहसुन के गिरे हुए दामों से परेशान हैं। कृषि मंडियों में अपनी उपज लेकर पहुंचे किसानों को लहसुन के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। रतलाम की प्रमुख कृषि उपज मंडियों में लहसुन की कीमत न्यूनतम 300 रुपए क्विंटल से अधिकतम 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रही है। ऐसे में किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही। यही वजह है कि कई किसान अपनी लहसुन की फसल फेंकने को मजबूर हो गए हैं। लहसुन के दामों में अप्रैल महीने से ही गिरावट दर्ज की जा रही है। लंबे समय तक अपनी फसल रोककर दाम बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं किसानों का सब्र टूट रहा है और मंडी में दाम नहीं मिलने से किसान परेशान है।

लहसुन के दाम नहीं मिलने से जिले के किसान हो रहे परेशान

सड़क पर फेंक रहे लहसुन

किसानों का एक बीघा में 20 से 22 हजार रुपए से अधिक तक का खर्च हो जाता है लेकिन लहसुन के दाम कम मिलने की वजह से किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। रतलाम लहसुन प्याज मंडी में लहसुन का न्यूनतम दाम 300 प्रति क्विंटल और अधिकतम दाम 2000 प्रति क्विंटल तक है। फसल का दाम नहीं मिलने पर किसान अपनी फसल को बेचे बिना वापस अपने घर लेकर जा रहे हैं। तो कुछ किसान बारिश में भीग चुकी फसल को रास्ते में ही फेंक रहे हैं।

मजदूरी भी नहीं निकल रही

दरअसल, इस वर्ष रतलाम जिले में बड़े रकबे में किसानों ने लहसुन की बोवनी की है। जिले की कृषि उपज मंडियों में लहसुन की बंपर आवक इन दिनों हो रही है। किसानों के अनुसार महंगे बीज, खाद, दवाई सिंचाई की व्यवस्था के बाद महंगे मजदूरों से लहसुन की हारवेस्टिंग करवाई। जिसके बाद दाम बढ़ने के इंतजार में किसानों ने भंडारण भी किया। लेकिन अब लहसुन के दाम नहीं मिलने से किसानों की लागत तो दूर मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है।

विरोध में लहसुन-प्याज की माला पहनी

अपनी उपज के उचित दाम नहीं मिलने से परेशान किसान नदियों में और सड़कों पर लहसुन फेंक रहे हैं। एक दिन जहां श्यामपुर के गांव हिंगोनी गांव के किसानों ने लहसुन से भरी दर्जनों बोरियां पार्वती नदी में फेंक कर अपना विरोध जताया। वहीं जावर क्षेत्र के किसानों ने लहसुन और प्याज की माला पहनकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। जिले में लहसुन और प्याज का अच्छा उत्पादन होता है। पिछले कुछ सालों से जिले में लहसुन और प्याज का रकबा लगातार बढ़ रहा है।

डीजल के दाम भी रुला रहे

इस साल अच्छा उत्पादन हुआ पर भाव सही नहीं मिल रहे हैं। डीजल के दाम भी अधिक हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी नहीं निकल रहा है। ज्ञापन देने वालों में नरपत सिंह ठाकुर, प्रदीप ठाकुर, रामचरण पाटीदार, राजेश महेश्वरी, दिनेश सेंधव, भूपेंद्र ठाकुर, राम सिंह प्रजापति, नरेंद्र ठाकुर, हरेंद्र ठाकुर आदि शामिल थे।

भावांतर का दिया जाए लाभ

ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने मांग की है कि कृषि उपज लहसुन एवं प्याज का निर्यात तुरंत प्रभाव से लागू करवाया जाए या भावांतर योजना का लाभ दिया जाए। राजस्थान की तर्ज पर बाजार हस्तक्षेप योजना को लागू करवाने की बात भी किसानों ने ज्ञापन में कही। किसानों का कहना है कि लहसुन की लागत 3000 रुपए क्विंटल से अधिक है, लेकिन मंडी में 300 रुपए से 600 रुपए क्विंटल ही मिल रहे हैं। इसी तरह प्याज की लागत हजार रुपए 2000 प्रति क्विंटल है, लेकिन मंडी में 500 से 800 रुपए प्रति क्विंटल ही प्याज बिक रहा है।

मप्र के गुना में पांच करोड़ की सब्जी वाला गांव, भटोदिया गांव में 90 फीसदी लोग उगा रहे सब्जियां

सब्जी वाला गांव

गुना। जागत गांव हमार

प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का गृह जिला गुना इन दिनों सुर्खियों के साथ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरलअसल, भटोदिया गांव गुना जिला मुख्यालय से 15 किमी दूर बसा है। यहां की आबादी करीब 600 है। गांव के एक-दो घर छोड़ दें तो सभी घर कच्चे थे। भटोदिया के किसान 2014 से पहले पारंपरिक खेती करते थे। गेहूं, सोयाबीन, चना आदि फसलें ही उगाते थे। लागत और आमदनी के बीच का अंतर लगातार कम हो रहा था। ऐसे में गांव के किसान विकल्प की तलाश कर रहे थे। 2014 में यहां के रहने वाले बनवारी लोधा ने पारंपरिक खेती छोड़ने का मन बनाया। यहां से बदलाव की शुरुआत हो गई। आज गांव में 90 प्रतिशत घर पक्के बन चुके हैं। बनवारी लोधा ने छोटे भाई नवजीवन लोधा को शिवपुरी के किसान के पास सब्जी की खेती की ट्रेनिंग लेने भेजा। दो से तीन महीने की ट्रेनिंग के बाद नवजीवन गांव लौटे। बड़े भाई बनवारी लोधा के साथ मिलकर 3 बीघा जमीन में सब्जी उगा दी। पहली ही बार में अच्छा मुनाफा हुआ तो बाकी जमीन में भी सब्जियां उगाने लगे। गांव में 90 परिवार हैं। सब्जी से अच्छी आमदनी होती देख करीब 75 किसान परिवार सब्जियों की खेती करने लगे हैं।

2014 में मेरे छोटे भाई रामजीवन लोधा ने शिवपुरी के एक किसान के यहां जाकर सब्जियां उगाने की ट्रेनिंग ली। वहां से लौटकर गिलकी और करेले की बोवनी की। तीन बीघा में लगभग 80 हजार रुपए की लागत आई। 80 से 90 दिन में फसल तैयार हो गई। उपज बेचने पर 2 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। यहीं से सब्जियां उगाने के सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी जारी है। पिछले वर्ष ढाई बीघा खेत में टिंडे लगाए। खेत तैयार करने से लेकर बोवनी और उसके रख-रखाव में 65 हजार रुपए की लागत आई थी। 45 से 55 दिन में टिंडे तैयार हो गए। बाजार में बेचने पर 12.50 लाख रुपए की इनकम हुई। यह अब तक कि सबसे ज्यादा इनकम थी।

अब दोनों भाई 9 बीघा में सब्जियां ही उगा रहे हैं। पौधे भी खुद ही तैयार करते हैं। करेला, खीरा, टमाटर, मिर्ची आदि सब्जियां उगा रहे हैं। आज उनकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो चुकी है। अब रोजाना की जरूरतों को आसानी से पूरा कर ले रहे हैं। साथ ही अच्छी इनकम होने से अपने शौक भी पूरे कर लेते हैं। उनकी खेती देखकर गांव के दूसरे किसान भी प्रभावित हुए और अब गांव के 90 फीसदी किसान पारंपरिक खेती छोड़ चुके हैं। बस उपयोग के लिए गेहूं की खेती करते हैं। इसके अलावा सब्जियां उगाकर शहर की मंडियों में भेजते हैं। इससे सभी किसानों को मुनाफा बढ़ा है।

राजस्थान का जायका बना रहा करेला

इसी गांव में रहने वाले एक अन्य किसान सुल्तान सिंह यादव कहते हैं कि रामजीवन से प्रेरणा लेकर सब्जियां उगानी शुरू की। आज वह अपने 5 बीघा खेत में करेला, गिलकी, लौकी, खीरा, बैगन, टमाटर उगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्वालियर की गाड़ी पूरा खीर ग्वालियर भेजते हैं। इसके अलावा राजस्थान के छबड़ा जिले सहित शिवपुरी, अशोकनगर और कई जिलों में इस गांव की सब्जियां पहुंचती हैं। शुरुआत में केवल बनवारी लोधा का परिवार ही सब्जियां उगाता था। उनके मुनाफे को देखते हुए धीरे-धीरे गांव के बाकी किसान भी अपने खेतों में सब्जियां उगाने लगे हैं। जिले में इस गांव को सब्जियों वाला गांव कहा जाने लगा है। जिले के हर घर में भटोदिया गांव में उगी हुई सब्जियां पहुंच रही हैं।

अब सभी किसान उगा रहे सब्जियां

वर्तमान में प्रदेश के कई जिलों में इसी गांव की सब्जियां पहुंचती हैं। पारंपरिक खेती को छोड़ गांव के सभी किसान अब सब्जियां ही उगा रहे हैं। केवल खाने के लिए गेहूं की खेती की जाती है, बाकी जमीन पर अब सब्जियों की पैदावार की जा रही है। आज यह गांव रोजाना डेढ़ से दो लाख रुपए की सब्जी मंडी में भेजता है।

गांव में रोजाना 2 लाख की सब्जी

अब इस गांव से रोजाना लगभग डेढ़ से दो लाख रुपए की सब्जी मंडी में पहुंचती है। इस तरह हर महीने लगभग 50 लाख रुपए की सब्जियों की पैदावार यह गांव कर रहा है। सालाना पैदावार की बात करें तो 5 करोड़ से ज्यादा की सब्जियां इस गांव में उगाई जा रही हैं।

किसान ऐसे तैयार कर रहे खेत

खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले गर्मियों के दिनों में खेत में प्लाऊ चलाया जाता है। इसके बाद इसे एक महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद मिट्टी को बारीक करने के लिए खेत में रोडर वेटर चलाया जाता है। इससे मिट्टी फूटकर बारीक हो जाती है। फिर इस जमीन में देशी खाद डाला जाता है। एक बीघा में लगभग 3-4 ट्रॉली खाद डालते हैं। उसके बाद बेड तैयार किए जाते हैं। एक बेड की चौड़ाई लगभग 3 फीट होती है। लंबाई खेत के हिसाब से कितनी भी हो सकती है। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 5 फीट रखी जाती है। फिर बेड पर देशी खाद डाला जाता है, उसके बाद रासायनिक खाद डाला जाता है। इसमें डीएपी, पोटाश, सल्फर शामिल होता है।

ड्रिप के लिए बिछाते हैं पाइप

बेड तैयार होने के बाद ड्रिप के लिए पाइप बिछाया जाता है। फिर उस पर पन्नियां बिछाते हैं। उसमे मल्चिंग कहा जाता है। इसके बाद पौधे लगाने के लिए छेंद किए जाते हैं। हर एक फीट पर एक छेंद होता है। छेंद होने के बाद बीज डाले जाते हैं या फिर पौधे रोपे जाते हैं। फसल के हिसाब से यह अलग-अलग होता है। कुछ सब्जियों के बीज लगते हैं तो कुछ के पौधे। इसके बाद सपोर्ट के लिए रस्सियां बांधी जाती हैं। बेड के दोनों किनारों पर लकड़ियों के पिलर बनाकर उस पर रस्सियां बांधी जाती हैं। फिर बेल के सपोर्ट के लिए इन रस्सियों के सहारे धागा बांधा जाता है, जिसे पकड़कर बेल ऊपर की तरफ बढ़ती है।

सब्जी की खेती में लागत 30 हजार

एक बीघा में सब्जी उगाने के लिए खेत तैयार करने में लगभग 25 से 30 हजार रुपए की लागत आती है। इसमें खेत तैयार करने से लेकर रखरखाव, पानी, बिजली, खाद, रासायनिक खाद शामिल होता है। बीज की कीमत अलग होती है। हर सब्जी के बीज की कीमत अलग-अलग आती है। जैसे एक बीघा में आधा किलो करेले का बीज लगता है। यह 5 हजार रुपए में आता है। इसी तरह बाकी सब्जियों के बीज की कीमत अलग होती है। कुल मिलाकर एक बीघा खेत में कुल लागत लगभग 35-40 हजार रुपए आती है। वहीं अगर पैदावार ठीक हुई और बाजार में कीमत अच्छी मिली तो 1.5 लाख तक की पैदावार होती है। सारा खर्चा काटकर एक लाख तक का शुद्ध मुनाफा होता है।

हल्दी की फसल में यूरिया की जगह ढैंचा बोया, नवाचार करने वाले 10 जिलों के किसान सम्मानित

खेत में नाइट्रोजन पैदा कर लेता है इंदौर का किसान

इंदौर। हल्दी की फसल में नाइट्रोजन की कमी दूर करने के लिए यूरिया की जगह ढैंचा बो दिया। इससे रासायनिक खाद का खर्च तो बचा ही, उत्पादन भी बढ़ गया। खेती में ऐसे ही नए-नए प्रयोग करने वाले 10 जिले के किसानों को 15 अगस्त को सरकार ने सम्मानित किया। इनमें इंदौर के सिमरोल के भी एक किसान शामिल हैं। सिमरोल के जितेंद्र पाटीदार कहते हैं, 5 साल पहले जैविक खेती करना शुरू किया। पिछले साल हल्दी की फसल में नाइट्रोजन की कमी दूर करने के लिए यूरिया की जगह ढैंचा का पौधा लगा दिया। यूरिया में सिर्फ 45 प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। वहीं ढैंचा जमीन में नाइट्रोजन की कमी ही दूर कर देता है। इससे एक बीघा में 2 लाख तक की आय हुई। यूरिया का इस्तेमाल करते तो जमीन खराब होती। साथ ही कमाई भी 1 लाख 25 हजार से ज्यादा नहीं होती। एक बार फसल तैयार होने के बाद ढैंचा को जमीन में ही नष्ट कर दिया जाता है।

इंदौर में 615 एकड़ में हो रही प्राकृतिक खेती

ट्रॉबेरी और केसर की भी खेती

इंदौर से सटे इलाकों में किसान पारंपरिक खेती के साथ ही ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, थाई पिंक अमरूद व केसर की खेती भी कर रहे हैं। जामली के पास शिक्षा व पर्यावरणविद प्रो. एसएल गर्ग ने करीब 25 एकड़ की बंजर पहाड़ी को केसर पर्वत नाम देकर यहां केसर की फसल लगाई है। इस वर्ष खरीफ सीजन में 1567 कृषकों ने प्राकृतिक खेती का पंजीयन कराया है। जिले में लगभग 615 एकड़ रकबे में प्राकृतिक खेती की जा रही है।

मिट्टी परीक्षण से शुरुआत करें

उद्यानिकी सलाहकार राकेश अहिरवार के अनुसार प्राकृतिक खेती के लिए अच्छी किस्म के बीज, पौधों का चयन जरूरी है। इसके पहले मिट्टी का भी परीक्षण कर लें। जलवायु अनुसार पौधों का रोपण करें। उद्यानिकी विभाग के अधिकारी त्रिलोकचंद वास्कले कहते हैं शासन की प्राकृतिक खेती की योजना के क्रियान्वयन पर जिले में विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भारत के कृषि क्षेत्र में बड़ी प्रगति के बाद भी किसान परेशान

रोहणी पांडेय
वरिष्ठ समाज सेवी एवं चिंतक

लगभग तीन दशक पहले मैं गन्ना किसानों द्वारा अपने बकाया भुगतान की मांग को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को कवर करने पंजाब के गुरुदासपुर में गया था। तीस साल बाद भी देश के कई हिस्सों में गन्ना किसानों को अपने बकाया भुगतान के लिए लंबे समय तक विरोध का सहारा लेते हुए देखना दुखद है। वे मुफ्त की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे चीनी मिलों द्वारा खरीदे गए गन्ने के समय पर भुगतान की वैध बकाया राशि की मांग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट और कुछ उच्च न्यायालयों ने चीनी मिलों को 14 दिनों में भुगतान करने का निर्देश दिया है और भुगतान में देरी होने पर 15 प्रतिशत का ब्याज देने का निर्देश दिया है। यह महत्वाकांक्षी भारत है, जहां इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हमें अक्सर बताया जाता है कि उद्यमशीलता की संस्कृति का विकास भारत की सफलता की कुंजी है। लेकिन ऐसा क्यों है कि जब हम युवा भारत की उद्यमशीलता की भूख की बात करते हैं, तो यह भूल जाते हैं कि गांवों के युवा भी महात्वाकांक्षी उद्यमी बनने के अवसर तलाश रहे हैं। वे भी नवाचार करने, अपने कौशल में सुधार करने और कृषि में क्रांति (पैमाने और दक्षता, दोनों में) लाने के इच्छुक हैं। ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भूख मिटाने की सबसे बड़ी बाधा किसानों को उनकी सही आय से वंचित करना है, और उन्हें उनके बकाये के भुगतान की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर करना है। किसानों के भी सपने होते हैं और जैसे-जैसे उनकी आय बढ़ती है, (उनमें अंतर्निहित जोखिम लेने की उनकी क्षमता को देखते हुए), वे तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर गन्ने जैसी फसल की खेती करने के बाद, जिसे तैयार होने में एक साल लगता है, उनमें से कई को मिलों से भुगतान प्राप्त करने के लिए महीनों या लगभग एक और साल तक विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ता है, तो यह निश्चित रूप से उड़ान भरने की उनकी आकांक्षा को मार देता है। हालांकि वर्ष 2020-21 में जब गन्ना सीजन खत्म हुआ था, तब किसानों का बकाया घटकर 6,667 करोड़ रुपए रह गया था, जो एक साल पहले 10,342 करोड़ रुपए था। बड़ा सवाल यह है कि चीनी मिलें समय पर भुगतान क्यों नहीं कर सकती हैं। मिलों का कहना है कि उत्पादन की लागत बढ़ गई है, क्योंकि गन्ने के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्च मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिससे सरकारें मिलों को बकाया चुकाने के लिए बार-बार सब्सिडी प्रदान करने के लिए मजबूर होती हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2017-18 में, सरकार ने बकाया राशि चुकाने के लिए संकटग्रस्त मिलों को 7,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया था। इसके अलावा, कई अन्य प्रोत्साहन हैं, जो सरकार समय-समय पर मिलों के लिए जारी करती रही है। पंजाब में, निजी चीनी मिलों को 2015-16 में 50 रुपये, वर्ष 2018-19 में 25 रुपए और 2021-22 में 35 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी प्रदान की गई थी। फिर भी, चार निजी मिलों से 126 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान हासिल करने के लिए किसानों को फगवाड़ा में लंबे समय से धरने पर बैठने का मजबूर होना पड़ा है। इसने पंजाब सरकार को निजी चीनी मिलों के ऑडिट का आदेश देने के लिए प्रेरित किया है, ताकि चीनी मिलों की अर्थव्यवस्था का पता चल सके। चीनी मिल लॉबी के

दबाव के आगे झुकने के बजाय देश की सभी निजी चीनी मिलों के ऑडिट का काम पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। मीडिया हर साल लंबित गन्ना बकाया राशि की खबरें प्रकाशित कर रहा है। यह अजीब नहीं है कि पिछले तीस वर्षों से, जब से मैं जानता हूं, मिलों द्वारा 14 दिनों के भीतर गन्ने का बकाया भुगतान करने का मुद्दा अनसुलझा है। यदि शहरों में उद्यमशीलता के निर्माण के लिए लालफीताशाही की बाधाएं दूर करना, खराब बुनियादी ढांचे में सुधार, समय पर व्यावसायिक, व्यापारिक एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करना पूर्व जरूरतें हैं, तो ग्रामीण इलाकों में महत्वाकांक्षी कौशल को उभारने के लिए किसानों को उनके उत्पाद का समय पर और सुनिश्चित भुगतान शीर्ष पर होना चाहिए। यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, जिसका हल न निकाला जा सके, बल्कि यह बताता है कि ग्रामीण सपनों की पूर्ति किस तरह हमारे नीति नियंताओं की प्राथमिकता में सबसे नीचे है। चाहे वह गन्ने का बकाया हो, या अचानक बाढ़ या बढ़ते तापमान से फसल को नुकसान या कुछ साल पहले सफेद मक्खी के कारण कपास की फसल को हुआ नुकसान, किसानों को सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए भूख हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरने का सहारा लेना पड़ता है। आखिर किसानों को किसी भी तरह की राहत या अपनी उपज के बेहतर मूल्य के लिए विरोध प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है। भारत ने पिछले 75 वर्षों में कृषि क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। मुझे लगता है कि ग्रामीण इलाकों में उद्यमशीलता का माहौल बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक गंभीर बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा कृषि क्षेत्र में व्यापार सुगमता सूचकांक लाना है। विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर, जिसमें भारत ने 80 पायदान की छलांग लगाई है, अब समय आ गया है कि भारत अपना खुद का ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग इंडेक्स तैयार करे। कृषि क्षेत्र की ज्यादातर समस्याएं शासन की कमी से जुड़ी हैं और बड़ी चुनौती है कि हर स्तर पर आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए, ताकि तंत्र को और अधिक किसान अनुकूल बनाया जा सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने न केवल उद्योग के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में मदद की, बल्कि रास्ते में आने वाली अनावश्यक बाधाएं भी दूर कीं। व्यावसायिक संचालन आसान बनाने के लिए छोटे-बड़े 7,000 कदम उठाए गए। आखिर भारत विश्व बैंक के प्रस्ताव का इंतजार करने के बजाय खुद का ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग इंडेक्स तैयार कर इसे सही तरीके से लागू करने की शुरुआत क्यों नहीं कर सकता। इसका अर्थ एक विस्तृत और कुशल प्रणाली स्थापित करना होगा, जो किसानों की हर समस्याओं का समाधान करे। इससे किसानों को बार-बार धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा और यह अंततः ग्रामीण उद्यमियों की नई पौध के उभरने में मदद करेगा।

योगी के राज में मेंथा की खेती से किसानों की आय हो रही दोगुनी

भरत लाल पांडेय
उन्नत किसान

किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले सिम उन्नति बीज दिए गए, उन्हें एसआरआई पद्धति का उपयोग करके फसल उगाने और संयंत्र में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करने की सलाह दी। इससे किसानों को काफी फायदा हुआ है। मेन्थॉल तेल उत्पादन बढ़ाने की इस पहल का नेतृत्व सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन कर रहा है।

भारत मेन्थॉल तेल का एक प्रमुख निर्यातक है और देश की लगभग 75 प्रतिशत मेन्थॉल फसल उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। हालांकि, इस साल मार्च में शुरुआती गर्मी ने मेंथा की फसल को भारी झटका दिया, क्योंकि किसानों ने कम उत्पादन की शिकायत की थी। गर्मी में अचानक वृद्धि के कारण मेंथा के पौधे की वृद्धि रुक गई जिससे कुल तेल उत्पादन प्रभावित हुआ हालांकि, उत्तर प्रदेश में मेंथा किसानों का एक समूह है, जो शुरुआती गर्मी और मौसम की अनिश्चितता के बावजूद अपने मेन्थॉल तेल उत्पादन को दोगुना करने में कामयाब रहा है। इन किसानों ने मेन्थॉल उत्पादन की उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन पद्धति की मदद से अच्छा उत्पादन पा रहे हैं। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले सिम उन्नति बीज दिए गए, उन्हें एसआरआई पद्धति का उपयोग करके फसल उगाने और संयंत्र में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करने की सलाह दी। इससे किसानों को काफी फायदा हुआ है। मेन्थॉल तेल उत्पादन बढ़ाने की इस पहल का नेतृत्व सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन कर रहा है। किसान कहते थे कि एक बीघा जमीन में दस किलो से अधिक तेल का उत्पादन नहीं हो सकता है, लेकिन अब यह धारणा बदल गई है। एक बीघा भूमि 0.619 एकड़ या 0.25 हेक्टेयर या 800 मीटर वर्ग के बराबर होती है। मेंथा की फसल आमतौर पर फरवरी-मार्च के दौरान लगाई जाती है और फसल जून-जुलाई में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। फिर फसल को एक दिन के लिए धूप में सुखाया जाता है और फिर आसवन प्रक्रिया के माध्यम से सूखी फसल से तेल निकाला जाता है। व्यापारियों को तेल करीब 1,000 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। पहले, किसान बेतरतीब ढंग से बीज बोते थे ताकि पौधे खेत में असमान रूप से विकसित हों। अब, श्री विधि (जड़ गहनीकरण विधि की प्रणाली) को अपनाया है, हमारे लिए खरपतवार निकालना आसान है। इसमें पौधे की वृद्धि घनी होती है। इससे किसानों को दोहरा लाभ मिल रहा है। एक बीघा मेंथा की फसल से आय 8,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए करने में कामयाब रहे। जमीनी स्तर के संगठन टीआरआईएफ ने बहराइच जिले के मिहीपुरवा ब्लॉक में कुल 20,000 मेंथा किसानों में से 4,500 को प्रशिक्षित किया है और ब्लॉक के कई गांवों में 55 किसानों के सहयोग से 50 प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किए हैं। प्रदर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में, टीआरआईएफ ने मेंथा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, नीम के तेल स्प्रे, उर्वरकों को प्राप्त किया और प्रदान किया। कटाई के दस दिनों से पहले स्टोलन उपचार और खेतों को सुखाने जैसी कुछ प्रथाओं को भी किसानों ने अपनाया था। जमीनी स्तर का संगठन किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसलों के गहनीकरण और विविधीकरण पर काम करता है। जड़ गहनीकरण प्रणाली के नए तरीके से किसानों की आय दोगुनी होने का दावा किया गया है। पिछले साल फसल से आठ लीटर तक तेल मिला था। इस साल, हम अठारह लीटर तक तेल की उम्मीद करते हैं। यह सब एसआरआई पद्धति के कारण संभव हुआ जिसने उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद की। मेंथा उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय दोगुनी करने की पहल में महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। मीरा, कविता, सरिता की तरह मिहीपुरवा प्रखंड की हजारों ग्रामीण महिलाओं को नई पद्धति से अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। कुल 2,064 एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) हैं, जिसमें ब्लॉक में 22,704 महिलाएं शामिल हैं। टीआरआईएफ द्वारा 4,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

रूढ़िवादी सोच में दबे पहाड़ के गांव

रूढ़िवादी सोच में दबे पहाड़ के गांव

जिन समस्याओं को लेकर हम इतने आश्वस्त हो चुके हैं कि उनके मुद्दे अब हमारे लिए खत्म हो गए हैं, उन समस्याओं ने उत्तराखंड के दूरस्थ पहाड़ी जिले बागेश्वर के गांवों में न जाने कितने सपनों और आकांक्षाओं को दबा रखा है। वर्ष 1997 से पहले बागेश्वर अल्मोड़ा जिले का हिस्सा हुआ करता था। विकास की रफ्तार को तेजी देने के लिए इस नए जिले को तीन विकास खंडों-बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट में विभाजित किया गया। पर दो दशकों से अधिक समय बीतने के बाद भी यह जिला कई समस्याओं से जूझ रहा है। गरुड़ विकास खंड के चोरसो गांव की लड़कियां कहती हैं कि उन्हें अपने सपने पूरे करने के अवसर ही नहीं मिलते, तो वे कहां से यह सोचें कि उनका विकास कैसे होगा। उन्हें स्कूल जाने के लिए सड़क अच्छी मिल जाए और बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाए, तो उन्हें लगेगा कि विकास हो रहा है। पर जब उनकी इन्हीं समस्याओं की तुलना घर के लड़कों से करने को कहा गया, तो उनके जवाब अलग थे। इसी जिले के एक अन्य विकासखंड कपकोट के एक गांव उत्तरौड़ा की रहने वाली लड़कियां लैंगिक असमानता पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं और कई परंपराओं पर सवाल भी करती हैं। यहां की कम ही लड़कियां नौकरी करती हैं, क्योंकि जितने मौके लड़कों को मिलते हैं, उतने मौके न तो उन्हें मिलते हैं, न ही परिवार के लोग उन पर खर्च करना चाहते हैं। इस गांव की ज्यादातर लड़कियों का कहना था कि कोई भी काम लिंग के आधार पर बंटा नहीं होना चाहिए। आजादी के 75 साल बाद भी हमने अपने समाज के अंदर न जाने कितने ही खोखले विचारों एवं रूढ़िवादी परंपराओं को जगह दे रखी है, जिनकी वजह से असंख्य लड़कियों की सपने देखने की आजादी तक छिन गई है। बघर भी कपकोट विकास खंड का एक गांव है, पर कनेक्टिविटी की समस्या से जूझता यह गांव अलग-थलग होकर रह गया है। गांव में न आंगनबाड़ी है, न ही किसी तरह का नेटवर्क आता है। पहाड़ी पर बसे इस गांव तक पहुंचने के रास्ते इतने संकरे और जोखिम भरे हैं कि मुश्किल से सुविधाएं पहुंच पाती हैं। यहां की लड़कियां बताती हैं कि पास में सिर्फ एक ही स्कूल है और अगर उसमें पढाई नहीं करनी, तो पैदल दो घंटे से

दो महीने के इंतजार के बाद किसानों को मिली बड़ी राहत

नर्मदापुरम में 72 केंद्रों पर मूंग की समर्थन पर हो रही खरीदी

-14 हजार किसानों ने अपनी उपज व्यापारियों को बेच चुके

नर्मदापुरम। जागत गांव हमार

जिले में 60 दिन की ग्रीष्मकालीन फसल मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो गई है। 72 केंद्रों पर 66 हजार किसानों से मूंग खरीदी जानी है, इसके लिए जिला प्रशासन व कृषि विभाग के द्वारा सभी केंद्रों पर व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसान मूंग की उपज निकालने के बाद 60 दिन तक इंतजार करते रहे। तब कहीं खरीदी शुरू हो सकी है। इस बीच करीब 14 हजार किसानों ने अपनी उपज व्यापारियों को कम दाम में घाटा खाते हुए बेच चुके हैं। उन किसानों के पास अब पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं है। बीते वर्ष 2021 में 2 लाख 8 हजार हेक्टेयर में मूंग की बोवनी हुई थी। 2022 में 2 लाख 25 हजार हेक्टेयर से मूंग की उपज निकाली गई है। इस बार 80 हजार से अधिक किसान पंजीयन कराते लेकिन मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी या नहीं इस असमंजस में जरूरत मंद किसानों ने व्यापारियों को बेच दी है।

वेयर हाउसों में की जा रही खरीदी: प्रशासन स्तर पर मूंग की खरीदी वेयर हाउस में या फिर वेयर हाउस के पास की जा रही है। जिससे मूंग की उपज वर्षा से खराब नहीं हो सके। पहले दिन 70 केंद्रों पर खरीदी शुरू हो गई थी। अब दूसरे दिन से सभी 72 केंद्रों पर खरीदी शुरू हो जाएगी।

खरीदी की घोषणा देरी से हुई: किसान नेता उदय पांडेय ने कहा कि शासन इस बार मूंग की खरीदी को लेकर शांत रहा। इससे किसानों को यह अंदाजा होने लगा था कि शासन स्तर से मूंग खरीदी शायद ही हो। इसी कारण किसानों ने मूंग निकालने के बाद एक पखवाड़े तक शासन द्वारा मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रतीक्षा की। जब घोषणा नहीं हुई और पंजीयन भी शुरू नहीं हुए तो कई किसानों ने कम दाम पर अपनी मूंग व्यापारियों को बेच दी। इस कारण कम ही किसानों ने पंजीयन कराया है।

14 हजार किसानों ने नहीं कराया पंजीयन

बीते वर्ष 80 हजार किसानों ने पंजीयन कराया था। इस बार सिर्फ 66 हजार ने कराया है। जिले के 14 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन ही नहीं कराया है। उन्हें कम से कम प्रति क्विंटल दो हजार रुपये का घाटा हुआ है। इस नुकसान को लेकर किसान खासे नाराज हैं। किसान नेता गणेश गौर का कहना है शासन को पहले ही खरीदी की घोषणा करना था।

सरकार से किसान नाराज

मूंग खरीदी में होने वाली लेटलतीफी होने से क्षेत्र का किसान शासन से नाराज है, क्योंकि किसानों को कम दाम में मूंग बेचने को मजबूर होना पड़ा है। किसानों ने बताया कि प्रति किसान 10 से 20 हजार रुपये के घाटे में रहे हैं।

समर्थन मूल्य 7225 रुपए तय

शासन के द्वारा मूंग का दाम 7225 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ है, लेकिन किसानों ने 5 से 6 हजार के भाव में मूंग बेच दी है। किसानों के सामने खरीफ की बोवनी के लिए खाद-बीज की जरूरत थी, इसलिए किसानों को नकद राशि चाहिए थी। किसान केशव साहू का कहना है कि यह भरपाई किसान कहां से करेंगे।

जिले के 72 केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो गई है। 66 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है। बैठक में सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खरीदी में किसी तरह से गड़बड़ी न हो, वरना कार्रवाई की जाएगी।

जेआर हेडाऊ, उप संचालक, कृषि नर्मदापुरम

-हाइवे से लेकर मंडी तक मवेशी

50 लाख रुपए की गौशाला पड़ी अधूरी

बानमोर। जागत गांव हमार

कस्बे में बेसहारा मवेशियों के प्रबंधन के लिए गोशाला निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस गौशाला का निर्माण अधूरा रहने से इसमें आज तक मवेशियों को नहीं भेजा गया है। ऐसे में यह बेसहारा मवेशी हाइवे से लेकर मुख्य बाजारों में उत्पात मचाकर लोगों को अपने सींगों का शिकार बना डालते हैं। भूखे रहने की वजह से यह सब्जी मंडी की ओर भी रुख कर लेते हैं।

जिसकी वजह से मंडी में ग्राहकों और दुकानदारों के लिए मवेशी किसी मुसीबत से कम नहीं हैं। यहां कई लोगों को अभी तक यह मवेशी सींग मारकर घायल कर देते हैं। उल्लेखनीय है कि बानमोर कस्बे में 50 लाख रुपए की लागत से नगर परिषद ने पवाया गांव में गोशाला का निर्माण कराना शुरू किया। लेकिन इस गौशाला का काम अधूरा ही रह गया। जिसकी वजह से इसका उपयोग नहीं हो पा रहा। आलम यह है कि यहां मवेशियों के लिए अभी तक पानी का इंतजाम नहीं किया गया है। इसके साथ ही अन्य कई निर्माण इसमें अधूरे पड़े हुए हैं। लेकिन इसके निर्माण को लेकर अब महीनों से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

आंदोलन भी अनदेखा

उधर कस्बे के मुख्य बाजारों से लेकर हाइवे पर सैंकड़ों और हजारों मवेशी मंडरा रहे हैं। जो आए दिन किसी न किसी हादसे का कारण बनते रहते हैं। यहां सब्जी मंडी में ही स्थानीय एक किराना दुकानदार बुजुर्ग महिला को सांड ने अपने सींगों का निशाना बनाकर घायल कर दिया। जिस पर उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। इसी तरह हाइवे पर इन मवेशियों से टकराकर कई दुपहिया वाहन चालक हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इन मवेशियों का प्रबंधन अभी तक नहीं हो पा रहा है। जबकि इस मामले को लेकर स्थानीय हिंदू संगठन नगर परिषद से कई बार मांग कर चुके हैं। इसके अलावा आंदोलन तक हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक न तो गौशाला संचालन को लेकर कोई प्रक्रिया शुरू हो सकी और न इन मवेशियों को लेकर कोई काम यहां हो सका।

उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नष्ट करना होगा गाजरघास

जबलपुर। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय गाजरघास जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर कई राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि अनुसंधान परिषद के समस्त संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) राज्यों के कृषि विभागों एवं अखिल भारतीय खरपतवार प्रबंधन के केंद्रों, स्कूल, कालेजों तथा समाजसेवी संस्थाएं शामिल हुई। इस अवसर पर खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के निर्देशक डॉ. जेएस मिश्र ने कहा कि गाजरघास मनुष्यों में अनेकों बीमारियों जैसे आंखों, त्वचा की एलर्जी, बुखार जानवरों और मनुष्यों में श्वांस संबंधी समस्याएं पैदा करने का कारण है। यह कृषि उत्पादकता को भी कम कर देती है गाजरघास की समस्या का समाधान जागरूकता एवं प्रशिक्षणों के माध्यम से ही किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि गाजरघास से ग्रसित जगहों में रहने वाले लोगों में त्वचा एवं श्वांस संबंधी रोगों में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि का कारण भी यही खरपतवार है। जानवरों में भी यह खरपतवार कई रोग फैला देता है। प्रगतिशील कृषकों एवं अन्य आमजनों से जनभागीदारी द्वारा गाजरघास मुक्त करने का आह्वान किया। कार्यक्रम संयोजक डॉ. सुशील कुमार ने गाजरघास से होने वाले प्रभावों और इसके नियंत्रण के उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। गाजरघास को खाने वाले कीट के बारे में बताया कि यह कीट जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहा है। गाजरघास से कम्पोस्ट बनाने की विधि को बताया तथा इसे अपनाकर कृषक अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

-नगर निगम में पहुंच रहीं शिकायतें, जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी

ग्वालियर में पौधरोपण के बाद नहीं हो रहा रखरखाव

ग्वालियर। जागत गांव हमार

शहर में बंपर पौधरोपण करने के बाद इन पौधों की देखभाल व रखरखाव नहीं हो रहा है। वार्ड चार के विभिन्न इलाकों में पौधरोपण के बाद पानी डालने तक की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके चलते पौधे पनप नहीं पा रहे हैं। इसकी शिकायतें अब नगर निगम के अफसरों के पास पहुंच रही हैं। हर साल पौधरोपण के बाद यही स्थिति होती है। इसके चलते 50 प्रतिशत तक पौधे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। इस वर्ष नगर निगम ने 50 हजार पौधे रोपने की लक्ष्य रखा है, लेकिन हालात यही रहे तो इनमें से आधे पौधे भी नहीं बच पाएंगे। हर वर्ष हजारों पौधे लगाने के बाद भी न तो ग्वालियर में भरपूर हरियाली छा सकी है और न ही प्रदूषण का स्तर कम होने जैसी कोई बात हुई है। नगर निगम हर बारिश से पहले हजारों पौधे लगवाता है। इस पर लाखों रुपए भी खर्च होते हैं। इसके बावजूद इनमें से आधे से अधिक पौधे देखरेख और सुरक्षा नहीं मिलने पर समय से पहले ही दम तोड़ देते हैं। नगर निगम का दावा है कि रोपे पौधों में से 10 से 20 प्रतिशत ही पौधे नहीं पनप पाते, लेकिन कई जगह यह आंकलन गलत नजर आता है।

पौधे पेड़ बनने की होड़ से बाहर

हालत यह है कि कई जगह पिछले वर्ष लगाए गए पौधों में से एक भी नहीं बचा है। हजारों पौधे पेड़ बनने की होड़ से बाहर हो चुके हैं। बारिश शुरू होते ही ऐसे कई स्थानों पर नगर निगम फिर पौधे लगा चुका है, लेकिन वहां भी अब रखरखाव नहीं किया जा रहा है। नगर निगम के पार्क विभाग के मुताबिक मानसून में पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय होता है। इस मौसम में पौधे 10 गुना तेजी से तैयार होते हैं और 30 गुना अधिक घने होते हैं। पौधे स्थानीय पर्यावरण की शर्तों के आधार पर लगाए जाते हैं।

50 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य

एक पौधे की कीमत 10 रुपए से 12 रुपए तक होती हैं, ऐसे में सालाना 6 से 7 लाख अधिक रुपए सिर्फ पौधारोपण पर खर्च किया जाता है। इस बार 50 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पीपल, गुलमोहर, चंपा, बाटल, कनैर, मेंहदी, तुलसी, नीम, इमली, शहतूत, जामुन, बरगद, अशोक समेत अन्य पौधे शामिल हैं। समाजसेवी राज चड्ढा के मुताबिक पौधे रोपने के बाद नगर निगम के अधिकारी निगरानी नहीं करते हैं, जिसका खमियाजा पौधों के साथ आम जनता को भी भुगतना पड़ता है।

-15 अगस्त 2023 तक बनाए जाने हैं 75 अमृत सरोवर

चार माह में बने सिर्फ छह अमृत सरोवर, 69 निर्माणाधीन

10 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है निर्माण

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर के तहत जिले में 75 नए अमृत सरोवर तालाब का निर्माण किया जा रहा है। इनका निर्माण कार्य अप्रैल 2022 में शुरू कर दिया गया था। लेकिन चार महीने बाद इनमें से सिर्फ छह अमृत सरोवर बनकर तैयार हुए हैं, जबकि 69 तालाब में काम चल रहा है।

इन सभी अमृत सरोवर को 15 अगस्त 2023 तक बनाकर तैयार करना है। इस तरह अब इनको पूरा करने के लिए महज एक साल का समय बचा हुआ है। इनके निर्माण के लिए मनरेगा योजना, 15वां वित्त और जनभागीदारी से लगभग 10 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है।

इन ग्राम पंचायतों में बने सरोवर

भोपाल जिले के ग्राम सूरजपुरा, गुनगा, खंडारिया, सिघौड़ा, कोलूखेड़ी खुर्द और बागसी में छह अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गए हैं। वहीं 69 तालाब का काम वर्षा की वजह से रुक गया है। अब वर्षा बंद होते ही इनमें काम शुरू कर दिया जाएगा। 21 तालाबों का इतना निर्माण कर लिया गया था कि उनमें वर्षा का जल एकत्रित हो जाए। अब इनके बंध मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इनके चारों तरफ पौधारोपण किया जा रहा है।

878 हेक्टेयर में होगी सिंचाई

अमृत सरोवर में न्यूनतम 10 हजार घनमीटर जलभराव होगा। सभी अमृत सरोवर के बन जाने पर इनमें 13 लाख 18 हजार घनमीटर जलभराव होगा। इनमें निर्माण कार्य से 878 हेक्टेयर कृषि भूमि की फसलों में सिंचाई हो सकेगी। वहीं इनका जल पशु-पक्षियों के पीने के लिए उपलब्ध रहेगा। साथ ही भूमिगत जल के स्तर में सुधार होगा। उपयोगकर्ता समूह द्वारा सिंचाई, मत्सयपालन एवं सिंघाड़ा, जल संवर्धन कार्य किया जाएगा। इससे उपयोगकर्ता समूह की आजीविका में बढ़ोत्तरी होगी।

जिले 75 अमृत सरोवर नए तालाब का कार्य अप्रैल महीने में शुरू किया गया था। अब तक छह तालाब बनकर तैयार हो गए हैं। बाकि अन्य निर्माणाधीन स्थिति में हैं। इनके बनने से इनमें होने वाले जलभराव से फसलों की सिंचाई होगी और गामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। यह सभी 15 अगस्त 2023 तक बनकर तैयार हो जाएंगे।

ऋतुराज सिंह, सीईओ, जिला पंचायत, भोपाल

दो करोड़ की जनभागीदारी

जिले की पंचायतों में बन रहे 75 नए तालाबों में लगभग दो करोड़ से अधिक की जनभागीदारी शामिल हैं। इसमें गांव के लोगों ने ट्रैक्टर, जेसीबी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। अब तक बने अमृत सरोवर में गुनगा और कढ़ैया चंवर के तालाब सबसे अधिक क्षमता वाले हैं। कढ़ैया का सरोवर 41 हजार 800 घनमीटर और गुनगा का 40 हजार 250 घनमीटर पानी की क्षमता वाला है। इसके अलावा ललरिया, दमिला, खंडारिया, कोटरा, परसोरा, के तालाब 12 हजार घनमीटर क्षमता वाले हैं। तो वहीं कोलूखेड़ी खुर्द का 16 हजार 59, गढ़ाकलां क 14 हजार 400, जमूसर कलां का 10 हजार, ग्राम पनया का 15 हजार 450, सुनगा का 14632, अंकिया का 39 हजार, सूरजपुरा का 20 हजार, सेमरा भैरोपुरा का 15 हजार और सिंघोड़ा के अमृत सरोवर की क्षमता 14 हजार 200 घनमीटर है।

-पौधारोपण किया, देशभर में चला रहा वननेस-वन अभियान

बैरागढ़ की कृषि उपज मंडी को हरा-भरा बनाएगा निरंकारी मिशन

भोपाल। जागत गांव हमार

संत हिरदाराम नगर के पास ग्राम भैंसाखेड़ी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उपज मंडी को निरंकारी मिशन हरा-भरा बनाएगा। यहां लगातार पौधरोपण किया जाएगा। निरंकारी मिशन ने सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से देश भर में वननेस-वन के तहत पौधारोपण अभियान शुरू किया है। इसी के तहत संत हिरदाराम नगर कृषि मंडी में पौधारोपण किया गया। इस अभियान में सन्त निरंकारी मिशन के सेवादारों एवम श्रद्धालुओं की विशेष भूमिका है। मिशन की ब्रांच बैरागढ़ से जुड़े सेवादारों ने यहां पौधारोपण किया, साथ ही उनकी नियमित रूप से देखरेख करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम संयोजक महेश वीधानी, अशोक नाथानी के मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में सेवादार मंडी पहुंचे और पौधारोपण किया। निरंकारी मिशन की स्थानीय शाखा प्रवक्ता कन्हैयालाल साधवानी के मुताबिक सतगुरु माता सुदीक्षा का कहना है कि प्राण वायु जो हमें इन वृक्षों से प्राप्त होती है, धरती पर इसका संतुलन बनाने के लिए हमें स्थान-स्थान पर वनों का निर्माण करना आवश्यक है, जिससे कि अधिक मात्रा में आक्सीजन का निर्माण होगा और उतनी ही शुद्ध वायु प्राप्त होगी। जिस प्रकार बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे लिए अनिवार्य है, उसी प्रकार से वृक्ष भी हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। साधवानी के अनुसार वननेस-वन नाम की परियोजना के अंतर्गत सम्पूर्ण भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर वृक्षों के समूह लगाए गए है जिनकी अधिक संख्या के प्रभाव से आसपास का वातावरण प्रदूषित होने से बचेगा ओर स्थानीय तापमान भी नियंत्रित रहता है। सभी पौधों को स्थानीय जलवायु एवम भौगोलिक परिवेश के अनुसार ही रोपा गया है।

ग्रोथ बढ़ाने की दवाई का फसलों पर पड़ा विपरीत असर, सब चौपाट

सरदारपुर। जागत गांव हमार

समीप की ग्राम पंचायत पटलावदिया में सोयाबीन फसल की ग्रोथ बढ़ाने की दवाई का विपरीत असर पड़ने का मामला सामने आया है। ग्रोथ बढ़ाने की दवाई का फसलों पर छिड़काव किया था, लेकिन छह किसानों की फसलें खराब हो गई। इसको लेकर किसानों ने कृषि सेवा केंद्र व दवाई कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई व नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि की मांग को लेकर कृषि विभाग कार्यालय में अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पटलावदिया के छह किसानों ने राजगढ़ के स्वराज कृषि सेवा केंद्र संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए दवाई लाकर 55 बीघा सोयाबीन फसल में छिड़काव किया था। सोयाबीन फसल की ग्रोथ होना तो दूर, इसके विपरीत सोयाबीन फसल में फूल व कर तक नहीं आए और सोयाबीन फसल बांझ-सी हो गई। किसानों ने बताया कि खराब फसलों को लेकर जब किसान सुंदरलाल, जगदीश, रामाजी आदि दुकानदार से मिले तो उन्होंने दवाई कंपनी में इसकी रिपोर्ट कर जांच दल बुलाने की बात कही थी, स्वराज कृषि सेवा केंद्र का जांच दल फसलों का मौका मुआयना करने नहीं पहुंचा।

किसानों ने कृषि विभाग में लिखित शिकायत दर्ज करवाकर फसलों का निरीक्षण कर पंचनामा आदि कार्रवाई कर संबंधित स्वराज कृषि सेवा केंद्र के संचालक व दवाई कंपनी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि की मांग की।

वरिष्ठ कार्यालय को पत्र भेजा

वरिष्ठ कृषि अधिकारी बीएस मंडलोई ने बताया कि ग्राम पटलावदिया के किसानों ने ग्रोथ बढ़ाने की दवाई से फसल खराब होने के संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कृषि विस्तार अधिकारियों से भी फसलों का निरीक्षण करवाया है। मैंने पटलावदिया पहुंचकर फसलें देखी हैं। वर्षा के चलते एक से दो खेतों की फसलों का ही निरीक्षण किया है। जांच का विषय होने से वरिष्ठ कार्यालय को पत्र भेजा गया है।

-पानी के रौद्र रूप के कारण गांव में किसानों का काफी नुकसान हुआ

कारम बांध के पानी से बर्बाद फसल की भरपाई करेगी सरकार

-धार में डैम को बचाने वालों का सीएम शिवराज ने किया सम्मान
-बोले-ये कोई कर्मकांड नहीं, मैं भी तीन दिन तक सो नहीं सका

भोपाल।

धार जिले के कारम बांध से पानी निकलने के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। किसान चिंता न करें, नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। इस घटना की जांच भी कराई जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बांध रिसाव के दौरान आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजसेवी, नागरिक संस्थाएं को प्रमाण पत्र और शाल देकर सम्मानित किया। इस दौरान पोकलेन मशीन आपरेटर, हेल्पर, ब्रेकर आपरेटरों शिवकुमार कोल, संजय भारती, मोहम्मद सैयद आलम, प्रमोद कुमार, सूरज कोल, नीतिश कुमार, अमित, जय सिंह, जितेंद्र दरबार, मोतीलाल, इंदु, गंगाराम, सुनील, श्यामलाल, विजय, संतोष ओसारी को राज्य सरकार की ओर से प्रमाण-पत्र और दो-दो लाख रुपए की सम्मान निधि का चेक भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वालों पर प्रदेशवासियों को गर्व है। टीम मध्य प्रदेश ने वैज्ञानिक आपदा प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह समन्वय का ही परिणाम रहा कि जनहानि नहीं हुई। हमने पशुहानि भी नहीं होने दी।

सीएम शिवराज ने कहा कि कारम डैम से पानी रिसने के मामले की जांच कमेटी गठित है। जो तथ्य निकलेंगे उसके आधार पर जहां कार्रवाई की जरूरत होगी वहां कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा संकट जिसने मुझे भी 3 दिन और 3 रात सोने नहीं दिया। कोई और चिंता ही नहीं थी। एक ही चिंता, जुनून, जज्बा था कि हमारे भाई-बहन, बेटा-बेटी सब सुरक्षित रहें। केवल इंसान ही सुरक्षित ना रहे, बल्कि मूक प्राणी जो बोल नहीं सकते, कोई गाय, भैंस, बैल बंधा रह गया हो, बकरा-बकरी रह गया हो वह भी सुरक्षित रहे। मैंने कलेक्टरों को कहा था कि मुर्गा-मुर्गी को भी सुरक्षित निकाल ले जाना। कहीं कोई जान नहीं जानी चाहिए।

फसलों का नुकसान हम करेंगे

सीएम ने कहा कि बाकी थोड़ा बहुत फसलों का नुकसान हुआ है, लेकिन काहे की चिंता। मामा तो है। कर देगा भरपाई इसमें क्या दिक्कत है। एक बहुत बड़ी आपदा को टालने में हम सफल हुए हैं। यह कार्यक्रम कोई कर्मकांड नहीं है। ये अंतरात्मा ने कहा कि शिवराज इनका तू सम्मान कर इसलिए मैंने आज आपको बुलाया है।

फसलों को हुआ नुकसान, मुआवजा मिलेगा

इधर, कोठीदा गांव में कारम नदी पर बने बांध से पानी निकलने के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। पानी के रौद्र रूप के कारण गांव में किसानों का काफी नुकसान हुआ है। कई गांवों में सुबह लोग पहुंचे तो अपने घर व खेत में काफी नुकसान देखा। कारम नदी से ग्राम कोठिदा, चोकी, जहांगीरपुरा, फरसपुरा, सिमराली, सागरियावार, सिरसौदिया सहित खरगोन जिले के गांवों में भी नुकसान हुआ है। कोठिदा में करीब 32 किसानों के खेतों में पानी घुसने से फसल पूरी तरह तबाह हो गई। वहीं एक मकान में पानी घुसने से अनाज व घरेलू सामान पानी में बह गया है। ग्राम चौकी और जहांगीरपुरा में करीब 26 किसानों के खेत व 3 कच्चे मकानों को नुकसान हुआ है। वहीं सिमराली एवं फरसपुरा में करीब 27 किसानों के खेत सहित फरसपुरा-गुजरी पुलिया का एक तरफ का हिस्सा बह गया।

-पढ़ने वाले विद्यार्थियों को होगा फायदा

बीयू में खुलेगा कृषि विज्ञान संस्थान

-ईसी की बैठक में नए सदस्यों के साथ पहली बैठक लिया गया था निर्णय

भोपाल।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) में कृषि विज्ञान संस्थान खोला जाएगा। कार्यपरिषद (ईसी) सदस्यों ने इसे मंजूरी दे दी है। विवि के अधिकारियों ने व्यवस्थाएं जुटाना शुरू कर दिया है। इसके लिए पांच सदस्यीय समिति भी गठित कर दी गई है। यह समिति दूसरे कृषि विज्ञान संस्थान से चर्चा कर व्यवस्थाओं को पुख्ता करेंगे। विवि में संस्थान खोलने के लिए नियमानुसार आईसीआर सहित अन्य अनुमतियां लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बीयू में पिछले दिनों नए सदस्यों के साथ ईसी की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसमें लगभग एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा कर अनुमति दी गई। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान संस्थान खोलने के आदेश दिए थे। प्रदेश में अब जबलपुर और ग्वालियर के बाद तीसरा एग्रीकल्चर कॉलेज बीयू में खुलेगा। ईसी ने इसके लिए अनुमति दे दी है। ईसी की अनुमति के बाद बीयू ने सारी औपचारिकताओं के साथ भवन निर्माण के लिए स्थान, फैकल्टी और अन्य पदों का सृजन, सीटों की संख्या आदि की तैयारी करेगा। इसके लिए पहले से चल रहे विवि व कॉलेजों से भी संपर्क किया जाएगा। राजधानी सहित अन्य प्राइवेट कालेजों में एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर डिग्री पहले से दी जा रही है।

विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा

बीयू में कृषि विज्ञान संस्थान खोलने के लिए तैयारी चल रही है। इस सत्र से विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जैविक खेती कोर्स को सबसे अधिक विद्यार्थियों ने यूजी के प्रथम वर्ष में दो साल में प्रवेश लिया है। अब कृषि विज्ञान संस्थान खोलने से विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। वे संस्थान में अनुभवी शिक्षकों के अंदर शोध कार्य भी कर पाएंगे। साथ ही जैविक खेती के तकनीक को भी समझ सकेंगे। कृषि विज्ञान संस्थान खोलने से विद्यार्थी कृषि के उपयोग में आने वाले तकनीकों के बारे में जान सकेंगे। इससे विद्यार्थी स्वरोजगार भी कर पाएंगे।

-नौकायान हुआ बंद होने से सैलानी मायूस

वेटलैंड सांख्यसागर झील में जलकुंभी ने रोकी राजकुमारी की चाल

शिवपुरी। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में स्थित सांख्यसागर झील में समय को जलकुंभी के कारण यहां पर नौकायान बंद हो गया है। इस झील में जलकुंभी बढ़ने के बाद पर्यटन विभाग द्वारा यहां पर चलाई जाने वाली बड़ी नौका राजकुमारी का संचालन बंद होने से पर्यटक मायूस हैं। पूरी झील में चारों तरफ जलकुंभी बढ़ गई है और यह धीरे-धीरे पूरी झील को इसने अपने में समेट लिया है। बीते कुछ दिनों से जलकुंभी यहां पर बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर नेशनल पार्क के अधिकारी व वन विभाग के अफसरों को इस पर ध्यान देना चाहिए। गौरतलब है कि इस साख्यसागर झील को पिछले दिनों रामसर साइट में चिंहित किया गया इसके बाद भी यहां पर इस झील की हालत खराब हो रही है। यह प्रदेश की दूसरी रामसर साइट है।

नौकायान बंद होने से पर्यटक मायूस

पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद इस समय पर्यटक विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आ रहे हैं, लेकिन साख्यसागर झील में नौकायन बंद हो जाने से लोगों को मायूसी हाथ लग रही है। यहां पर घूमने आने वाले पर्यटकों का कहना है कि जलकुंभी के कारण जो नौकायन बंद हुआ है उस पर जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। गौरतलब है कि नौकायान के लिए लाई गई वोट राजकुमारी का संचालन पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है। पिछले दिनों पर्यटक विभाग के अधिकारियों ने इस झील में जलकुंभी बढ़ने के बाद राजकुमारी नौकायन का संचालन बंद हो जाने के बाद इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

-20 करोड़ से अधिक का राहत बांटी, लेकिन नहीं भरे बाढ़ पीड़ितों के जख्म

अब तक मुआवजे के लिए भटक रहे डेंडरी गांव के 20 से अधिक किसान

लेमराज मौर्य, शिवपुरी।

कहते हैं कि समय बड़े से बड़े जख्मों को भर देता है। लेकिन शिवपुरी में पिछले साल आई बाढ़ के पीड़ितों पर यह कहावत सटीक नहीं बैठती है। बाढ़ को एक साल बीत जाने के बाद भी इनके जख्म ताजा हैं, क्योंकि इन पर प्रशासनिक राहत का मलहम ही नहीं लग पाया है। पिछले साल अगस्त की शुरुआत में लगभग आधा जिला बाढ़ की चपेट में था। जिले के 1300 से अधिक ग्रामों में हजारों लोग फंस गए थे। जिन्हें रेस्क्यू कर निकाला गया। इस दौरान हजारों लोगों के घर भी ढह गए थे। इसके बाद करीब 20 करोड़ रुपए की राहत राशि पीड़ितों को वितरित की गई थी। इसके बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद नहीं मिली है। बाढ़ प्रभावित नरवर के ग्राम पीपलखाड़ी के ग्रामीणों ने बताया कि कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस गांव में करीब 300 परिवार रहते हैं। बाढ़ के समय सभी लोगों को गांव छोड़कर ऊपर पहाड़ पर जाना पड़ा था। इसके बाद कई नेता और अधिकारी आए व मदद का आश्वासन दे गए, लेकिन सालभर बाद भी मदद नहीं मिली।

राजस्व की लापरवाही

बाढ़ में हुए नुकसान के सर्वे का काम राजस्व विभाग के पटवारियों को करना था। उन्होंने बिना मौके पर जाए सर्वे रिपोर्ट बना दी जिसके कारण कई पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया। वहीं कुछ लोगों को नुकसान के बिना भी राहत मिल गई। राहत राशि के वितरण के बाद भी करीब 40 हजार आवेदन नोडल महिला एवं बाल विकास विभाग के पास आए थे। यह आवेदन भी रद्दी का ढेर बनकर रह गए।

किसानों को नहीं मिला मुआवजा

शिवपुरी तहसील में आने वाले ग्राम डेंडरी में करीब दो दर्जन किसानों की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई थी। पटवारी ने इसका सर्वे भी किया था। लेकिन एक साल बाद भी इन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। करीब 20 किसानों ने इसे लेकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी की है और इसका भी आज तक समाधान नहीं हुआ है। कई बार तहसीलदार ने निराकरण होने की बात कहकर शिकायत भी कटवा दी, लेकिन किसानों ने शिकायत को वापस नहीं लिया।

-आदिवासियों की योजना में सामान्य वर्ग को दिया फायदा

जैविक खेती में 110 करोड़ का घपला!

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय को जैविक खेती से जोड़ने के लिए चलाई गई योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। केन्द्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साल 2016-17 में प्रदेश के आदिवासियों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 54 करोड़ मंजूर किए। इसी प्रकार विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया, सहरिया) के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। इसके अलावा राज्य मद से 36 करोड़ दिए गए हैं। केन्द्र सरकार को भेजे गए प्रोजेक्ट में सेसबानिया बीज की जगह सेसबानिया रोस्ट्रेट नामक बीज का नाम शामिल किया गया, जबकि सेसबानिया रोस्ट्रेट नामक बीज भारत में जैविक खेती के लिए केन्द्र सरकार की परम्परागत कृषि विकास योजना की गाइड लाइन में शामिल नहीं है। राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए संचालित जैविक खेती योजना में 100 करोड़ रुपए से अधिक का घपला सामने आया है। गौरतलब है कि कांग्रेस के विधायक डॉ. अशोक मर्सकोले ने भी इस मामले को विधानसभा में उठाया था।

आरटीआई से चौंकाने वाला खुलासा

केन्द्र सरकार से सेसबनिया रोस्ट्रेटा (टेंडर दर 114 रुपए प्रति किलो) मंजूर कराया गया, जबकि वितरण के समय मंडला जिले में 25 से 30 रुपए किलो मिलने वाला बीज बांटा गया। केन्द्र से दो अलग-अलग राशियां 54 करोड़ आदिवासियों के लिए और 20 करोड़ बैगा, भारिया, सहरिया के लिए मिली थी, इसका उपयोग अलग-अलग हितग्राहियों के लिए होना था। इसमें 36 करोड़ की राशि राज्य मद से भी जोड़ी गई थी, लेकिन आरटीआई में मिली किसानों की सूची में डिंडोरी, अनूपपुर और मंडला में दोनों मदों की राशि में एक ही सूची मिली, जिससे आशंका है कि एक आदिवासी को फायदा देने के नाम पर दो जगह भुगतान किया गया है।

कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग

मप्र कांग्रेस के नेताओं ने मांग की है कि पूरे मंडला जिले में रेन्डम तरीके से ज्यादा से ज्यादा गांवों की जांच कराई जाए। यह योजना प्रदेश के 20 आदिवासी बाहुल्य जिलों में संचालित की गई थी जांच में मंडला जिले में जिस तरीके का भ्रष्टाचार सामने आया। उसी तरह दूसरे 19 जिलों की भी जांच कराई जाए। योजना में आदिवासी जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग कर बेचने की बात कही गई थी, लेकिन एक भी उपज की ब्रांडिंग नहीं की गई। करीब 110 करोड़ रुपए का बंदरबाट हुआ है।

-दिल्ली से आता था नकली माल, इंदौर में कंपनी के थैलों में कर रहे थे री-पैक

प्रदेश के सिहोर, भोपाल, होशंगाबाद और इटारसी में की जा रही थी सप्लाय

तीन राज्यों में फैली नकली खाद की जड़

इंदौर। इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने नकली खाद बनाने वाले गोदाम पर छापामार कर चुकी पुलिस एक माह में एक दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कच्चा माल आने और मशीन में बनाने से जुड़े आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है। अभी करीब 10 आरोपियों की गिरफ्तारी और बाकी है। इनकी तलाश की जा रही है।

पूछताछ के बाद पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक नकली खाद की कड़ियां तीन राज्यों के कई जिलों से जुड़ी है। पुलिस को जांच में पता चला कि राजस्थान, दिल्ली, मध्यप्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में आरोपियों का नेटवर्क फैला है। नकली खाद प्रदेश में सिहोर, भोपाल, होशंगाबाद, इटारसी में सप्लाय की जा रही थी। रायपुर में भी पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

एक दर्जन पकड़ाए

पूछताछ में और आरोपियों के नाम सामने आए थे। ये दिल्ली, राजस्थान और बड़वाह इलाके के रहने वाले हैं। इनकी निशानदेही पर पुलिस अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में अब तक प्रहलाद गुर्जर, पर्वत सिंह, प्रवीण गर्ग, अंकित मित्तल, लखन बैरागी, कालू, मनोहर, शोएब अंसारी, सतीश और पंकज को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सभी नकली खाद सप्लायर, मशीन बनाने वाले कारीगर, दलाल और बाजार में बेचने वाले आरोपी हैं। इस केस में पुलिस को अभी करीब एक दर्जन और लोगों की गिरफ्तारी करना है।

यह है मामला

टीआई शशिकांत चौरसिया की टीम ने नकली डीएपी बनाने वाले गोदाम पर कार्रवाई की थी। यह कार्रवाई आरटीओ के नजदीक एम्पायर विवट्री कॉलोनी के निर्माणाधीन गोदाम में की गई थी। यहां नकली डीएपी को कंपनी के बोरों में भरकर ट्रक से सिवनी भेजने की तैयारी थी। इस मामले में पुलिस ने सचिन कटारिया ओर राजू बिरथरे को पकड़ा था।

जल्द होगा वन मंडल से एमओयू साइन

विक्रम विवि में मियावाकी तकनीक से होगा पौधरोपण

उज्जैन। जागत गांव हमार

विक्रम विश्वविद्यालय अपने परिसर में और शहर के विभिन्न स्थानों पर मियावाकी तकनीक से पौधे रोपेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय जल्द वन मंडल से एमओयू साइन करेगा। कुलपति प्रो. अखिलेशकुमार पांडेय और वन मंडल अधिकारी डॉ. किरण बिसेन ने इस संबंध में बैठक की। जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के साथ वन विभाग द्वारा विकसित किए जा रहे नगरीय वनीकरण ग्रीन क्षेत्रों का भ्रमण किया। विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया। कुलपति ने कहा कि विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए यह तकनीक जैव विविधता, पौधरोपण, अपशिष्ट जैवोपचारण, समस्याग्रस्त मिट्टी एवं जलभराव के उपचार एवं प्रबंधन में उपयोगी है। डॉ. बिसने ने कहा कि मियावाकी तकनीक जापान के वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस तकनीक के द्वारा बहुत कम समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस विधि में देशी प्रजाति के पौधे एक दूसरे के समीप लगाए जाते हैं जो कम स्थान घेरने के साथ ही अन्य पौधों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। पौधों की सघनता के कारण यह पौधे सूर्य की रोशनी को धरती पर आने से रोकते हैं जिससे धरती पर खरपतवार नहीं उग पाते हैं

इस विधि में झाड़ी, पेड़, छोटे पेड़ तथा कैनोपी आदि 4 समुदाय के लगभग 70 से अधिक प्रजाति के पौधों का रोपण वर्ष 2020 में भीतरी, भैरवगढ़ एवं मक्सी रोड औद्योगिक क्षेत्र में किया गया था।

अध्ययन के लिए उपयोगी

यह क्षेत्र मात्र 2 वर्ष में पौधे विकसित होकर एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित हो चुका है जिसमें कई प्रकार के पक्षी, कीट, मोलस्क, रेप्टाइल, मधुमक्खियां, तितलियां आदि अपना आवास बना चुके हैं। यह पारिस्थितिकी विद्यार्थियों के लिए जैव विविधता के अध्ययन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

मिलकर करेंगे काम

मुख्य वन संरक्षक मनोज अग्रवाल ने कहा कि नगरीय वनीकरण के लिए प्रयुक्त की जा रही मियावाकी तकनीक में विक्रम विवि एवं वन विभाग मिलकर कार्य करेंगे। यह तकनीक विद्यार्थियों को शोध कार्य में उपयोगी होगी। उज्जैन वन विभाग द्वारा अपशिष्ट निस्तारीकरण स्थल में भी इस तकनीक द्वारा पौधरोपण करते हुए भूमि उद्धार का प्रयास किया जा रहा है।

किसानों की बढ़ेगी आय

कुलानुशासक प्रो. शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि मियावाकी पद्धति के उपयोग से स्थानीय पारिस्थितिकी में सुधार आएगा तथा इसके द्वारा किसान की आर्थिक प्रगति भी होगी। यह तकनीक विवि में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अध्ययन एवं शोध के लिए उपयोगी होगी।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)